



सत्ता पक्ष पर चुनावी मोड़ में रहने का आरोप, कांग्रेस सांसद प्रणिती शिंदे बोलीं- लोकलुभावन योजनाओं से बढ़ रहा कर्ज

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद प्रणिती शिंदे ने सोमवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार चौबीसों घंटे "चुनावी मोड़" में रहती है और हर चुनाव से पहले अनियोजित लोकलुभावन योजनाओं के तहत पैसा बांटती है, जिससे देश और राज्यों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है।

'वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों' पर चर्चा के दौरान शिंदे ने महाराष्ट्र में हाल की बाढ़ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पैकेज को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ केंद्र प्रस्ताव न मिलने की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर राज्य के मंत्री पैकेज न मिलने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने किसानों को मिलने वाली

सहायता राशि को नाकाफी बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित पैकेज किसानों के साथ मजाक है। शिंदे ने आरोप लगाया कि एक किसान के खाते में मात्र छह रुपये जमा किए गए। उन्होंने केवाईसी और आधार लिंक की जटिल शर्तों में ढील देने की मांग की और मुख्यमंत्री राहत कोष से 100 करोड़ रुपये में से शेष धन के उपयोग पर सवाल उठाया। शिंदे ने दावा किया कि आज देश में हर बच्चा जन्म लेते ही सवा लाख रुपये के कर्ज के बोझ के साथ पैदा हो रहा है।

कांग्रेस सांसद ने महाराष्ट्र में जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। वहीं, तृणमूल कांग्रेस की प्रतिमा मंडल ने पश्चिम बंगाल को केंद्रीय योजनाओं का धन न मिलने का मुद्दा उठाया।

अम्मान/नई दिल्ली | जॉर्डन में पीएम मोदी-किंग अब्दुल्ला की अहम मुलाकात

जॉर्डन में पीएम मोदी-किंग अब्दुल्ला की अहम मुलाकात, आतंकवाद से लेकर नागरिक परमाणु सहयोग तक 8 बिंदुओं पर बनी सहमति

नई दिल्ली | अम्मान/नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। सोमवार शाम अम्मान स्थित अल हुसैनिया पैलेस में जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच भारत-जॉर्डन द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक और सार्थक बातचीत हुई।

बैठक के दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद-रोधी प्रयास, उर्वरक और कृषि, बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।

वार्ता के बाद किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में आधिकारिक राजकीय भोज का आयोजन किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यह यात्रा भारत-जॉर्डन संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम साबित होगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि अम्मान में किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ उनकी चर्चा बेहद सकारात्मक रही। उन्होंने भारत-जॉर्डन के विशेष और भरोसेमंद संबंधों को मजबूत करने के प्रति जॉर्डन के नेतृत्व की प्रतिबद्धता की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो भविष्य के सहयोग के लिए नई प्रेरणा देगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देशों ने संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए आठ

सूत्रीय योजना पर सहमति बनाई है। इसमें व्यापार एवं आर्थिक सहयोग, उर्वरक और कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचा, महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज, नागरिक परमाणु सहयोग तथा जन-जन संपर्क शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा 37 वर्षों में जॉर्डन की पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है। भारत और जॉर्डन के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 2.8 अरब अमेरिकी डॉलर का है। जॉर्डन भारत को फॉस्फेट और पोटैश जैसे उर्वरकों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, जबकि यहां करीब 17,500 भारतीय प्रवासी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

मध्य प्रदेश याचिका में 1,612 दिन की देरी माफ करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी



नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार की ओर से दीवानी याचिका में 1,612 दिनों की देरी माफ करने पर नाराजगी जताई है। जस्टिस जेबी पांडीवाला और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने 1 सितंबर को सरकार से सही कारण पूछे बिना देरी माफ कर दी। पांच दिसंबर के आदेश में पीठ ने स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार देरी माफ करने के लिए उचित कारण होना अनिवार्य है। एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कोविड महामारी को कारण बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश रद्द कर मामले पर नया आदेश जारी करने को कहा।

तीन साल बाद प्रियंका गांधी से प्रशांत किशोर की मुलाकात; कांग्रेस से पुरानी अनबन के बीच सियासी अटकलें तेज

कांग्रेस से पुरानी अनबन के बीच सियासी अटकलें तेज

नई दिल्ली: जन सुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ किसी नए समझौते की ओर बढ़ सकते हैं या फिर पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, फिलहाल दोनों पक्षों ने इस मुलाकात को सामान्य बताते हुए किसी भी राजनीतिक संकेत से इनकार किया है।

प्रियंका गांधी ने इस मुलाकात को लेकर सवाल को टालते हुए कहा कि यह कोई बड़ी खबर नहीं है, जबकि जन सुराज की ओर से भी इसे औपचारिक भेंट बताया गया। बावजूद इसके, राजनीतिक विश्लेषक इस मुलाकात को अहम मान रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब प्रशांत किशोर खुद को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस उत्तर भारत में अपनी खोई राजनीतिक जमीन वापस पाने की रणनीति पर काम कर रही है।

यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि तीन साल पहले कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच बातचीत टूट गई थी। उस दौरान पीके ने कांग्रेस नेतृत्व की रणनीति पर खुले तौर पर सवाल उठाए थे और बाद में बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस सहित एनडीए और महागठबंधन-दोनों के खिलाफ मोर्चा खोला था। हालांकि, जन सुराज को बिहार में करारी हार का सामना करना पड़ा और पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी।

प्रशांत किशोर का गांधी परिवार से पुराना संबंध रहा है। अप्रैल 2022 में उन्होंने सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस नेतृत्व के सामने पार्टी को पुनर्जीवित करने का रोडमैप पेश किया था। बाद में उन्हें एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल होने का प्रस्ताव मिला, जिसे उन्होंने अधिकार और स्वतंत्रता की कमी का हवाला देते हुए ठुकरा दिया। इसी के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। अब प्रियंका गांधी से हुई ताजा मुलाकात ने एक बार फिर प्रशांत किशोर और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर नए राजनीतिक कयासों को जन्म दे दिया है।



त्योहारों में महंगे हवाई किराए का मुद्दा संसद में उठा, मंत्री बोले- जरूरत पड़ने पर प्राइस कैपिंग करती है सरकार

नई दिल्ली: राज्यसभा में त्योहारों और विशेष अवसरों के दौरान हवाई किराए में बढ़ोतरी का मुद्दा जोरशोर से उठा। केरल से सीपीआई सांसद पी. संदोष के सवाल पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि हवाई किराए मांग और आपूर्ति पर आधारित होते हैं, इसलिए पर्वों के समय इनमें वृद्धि देखी जाती है।

मंत्री ने बताया कि हालिया इंडिगो संकट के दौरान सरकार ने प्राइस कैपिंग

जैसे कदम उठाकर यात्रियों को राहत दी थी। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में मंत्रालय सभी पहलुओं पर नजर रखता है और एयरलाइंस समेत सभी पक्षों से संपर्क बनाए रखता है। जरूरत पड़ने पर यात्रियों के हित में तत्काल निर्णय लिए जाते हैं।

नायडू ने कहा कि कुंभ मेला, कोविड महामारी और पहलगाम हमले जैसी परिस्थितियों में भी सरकार ने किराए नियंत्रित करने के उपाय किए हैं। डीजीसीए

की टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट सभी रूट पर किराए की निगरानी कर रही है।

उन्होंने बताया कि यदि किसी यात्री को टिकट की कीमत अत्यधिक लगती है तो वह स्क्रीनशॉट के साथ एयरसेवा पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकता है। यात्रियों के अधिकारों के लिए CAR और 'पैसेंजर चार्टर' जैसे स्पष्ट मैकेनिज्म पहले से मौजूद हैं, जिनके तहत देरी या उड़ान रद्द होने पर सुविधाओं का प्रावधान है।



परमाणु ऊर्जा में निजी कंपनियों के लिए दरवाजे क्यों खोल रहा है भारत? जानिए क्या है 'शांति विधेयक 2025'

सरकार का कहना है कि भारत ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट (GW) परमाणु ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा ढांचे में केवल सरकारी संस्थानों के भरोसे इस लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल है। ऐसे में निजी क्षेत्र की भागीदारी को जरूरी माना जा रहा है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी कंपनियों की अहम भूमिका है, और भारत भी वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य के अनुरूप खुद को मजबूत करना चाहता है।

क्या है शांति विधेयक 2025?

यह विधेयक परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 को निरस्त कर एक नया और व्यापक कानूनी ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव करता है। इसके तहत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को केवल सरकारी नियंत्रण से निकालकर "सरकार द्वारा विनियमित, निजी भागीदारी वाले मॉडल" की ओर ले जाने की योजना है। सरकार का दावा है कि इससे बिजली उत्पादन बढ़ेगा, ग्रिड एकीकरण आसान होगा और नवीकरणीय ऊर्जा के साथ संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।

1962 के अधिनियम से कैसे अलग है नया कानून?

परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 ने इस पूरे क्षेत्र को पूरी तरह केंद्र सरकार के नियंत्रण में रखा था, जिससे निवेश और तकनीकी विस्तार की रफ्तार धीमी रही। शांति विधेयक का उद्देश्य इस केंद्रीकृत मॉडल को बदलना और निजी क्षेत्र को सीमित

लेकिन नियंत्रित भूमिका देना है।

क्या विदेशी निवेश को मिलेगी अनुमति?

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में 49 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। इससे सरकार घरेलू नियंत्रण बनाए रखते हुए वैश्विक पूंजी और अत्याधुनिक तकनीक को आकर्षित करना चाहती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि कड़े नियमन और सुरक्षा मानकों के साथ निजी भागीदारी भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को नई गति दे सकती है। हालांकि, विपक्ष इसे संवेदनशील क्षेत्र बताते हुए सावधानी बरतने की मांग कर रहा है।

महाराष्ट्र में BMC और महानगरपालिका चुनाव: तारीखों पर नई स्थिति एवं राजनीतिक-लोकतांत्रिक प्रभाव

संपादकीय... |

महाराष्ट्र में लोकतंत्र की नींव मजबूत करने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर लंबे समय से लंबित प्रश्नों का समाधान अब धीरे-धीरे रूप ले रहा है। आज राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने मुंबई महानगरपालिका (BMC) सहित कुल 29 नगर निगमों के चुनावों के लिए तारीखें घोषित कर दी हैं। इसके साथ ही राज्य भर की नगरीय प्रशासन व्यवस्था पर लोगों की उम्मीदें और राजनीतिक दलों के रणनीतिक कदम दोनों सक्रिय हो गए हैं।

1. चुनाव की तारीख घोषित — जनवरी 2026

सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्रिहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के चुनावों की वोटिंग 15 जनवरी 2026 को होनी तय की गई है, और मतगणना 16 जनवरी 2026 को आयोजित होगी। यह ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अभी-अभी किया गया है, जिससे लंबे समय से प्रतीक्षित नगर निगम चुनावों को एक निश्चित समयरेखा मिल गयी है।

इस घोषणा का मतलब यह हुआ कि पिछले कई वर्षों से स्थगित और विवादों के बीच लटके चुनावों को अब एक ठोस तारीख मिल गयी है। इससे न केवल राजनीतिक दलों के लिए अपनी तैयारियाँ सुनिश्चित हुई हैं, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान और विश्वास बहाल करने का संकेत है।

2. चुनाव में अधिक निवेश और संसाधन मंजूर

चुनावों की ओर बढ़ते कदम के बीच, राज्य सरकार ने नगरीय निकायों के विकास और बुनियादी सुविधाओं के सुधार के लिए लगभग ₹112 करोड़ की मंजूरी भी दी है, जिसमें से ₹57 करोड़ से अधिक राशि सीधे BMC को आवंटित की गयी है। इस रकम का उपयोग फुटपाथ निर्माण, सीवरेज सिस्टम, नलों और नालियों की व्यवस्था आदि में किया जायेगा — यह तैयारियाँ चुनाव से पहले ही नगरीय जीवन स्तर को बेहतर बनाने का संकेत देती हैं।

3. चुनावों का राजनीतिक-लोकतांत्रिक महत्व

स्थानीय निकाय चुनाव केवल प्रशासनिक प्रतिस्पर्धा नहीं हैं — ये राजनीति की दिशा और जनता की प्राथमिकताओं की पहचान का प्रमुख मंच हैं। महाराष्ट्र में BMC, पुणे, नागपुर, ठाणे जैसे महानगरपालिका की राजनीति का प्रभाव न केवल स्थानीय स्तर पर दिखता है, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में भी अहम माना जाता है।

राजनीतिक दलों के लिए यह चुनाव भाजपा, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सहित अन्य छोटे दलों के बीच प्रभाव के समीकरण को बदल सकता है। पिछले वर्षों में BMC चुनावों की लगातार देरी को लेकर आलोचना होती रही है कि इससे प्रशासन लोकतांत्रिक जवाबदेही से दूर चलता है और स्थानीय नागरिक समस्याओं पर असर पड़ता है। ऐसे में चुनाव तारीख का ऐलान बड़ी लोकतांत्रिक जीत के रूप में देखा जा रहा है।

4. चुनावी प्रक्रिया में देरी के कारणों पर विचार

स्थानीय निकाय चुनावों में देरी की मुख्य वजह नामांकन प्रक्रिया पर फैसलों का समय-समय पर लंबित रहना, आरक्षण मोर्चे पर अदालत में चल रहे मामले, तथा निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुपालन से जुड़ी जटिलताएँ रही हैं। इन कारणों से पहले कुछ मतदान को दिसंबर 2025 के लिए टाला गया था और परिणामों की घोषणा को भी उच्च न्यायालय ने 21 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था, ताकि परिणामों का चरणबद्ध असर दूसरे चरण के मतदान को प्रभावित न करे।

इन पीछे की राजनीतिक और विधिक जटिलताओं ने यह स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में निर्वाचन-प्रक्रिया की पारदर्शिता और सही समय पर पालन होना कितना ज़रूरी है, तभी जनता के विश्वास में वृद्धि होती है।

5. नागरिकों और युवाओं के लिए संदेश

अब जब चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं, तो नागरिकों और विशेष रूप से युवाओं को चाहिए कि वे मतदाता सूची की जांच, मतदान के महत्व को समझना और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना शुरू करें। स्थानीय निकाय चुनावों में वोट डालना केवल एक अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है, क्योंकि इससे नगरों की स्वच्छता, जल-वितरण, सड़क बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी रोज़मर्रा की समस्याओं में सुधार आता है।

स्थानीय सरकारें सीधे नागरिकों के जीवन को प्रभावित करती हैं। इसलिए इस बार के चुनावों में नागरिकों की भागीदारी रिकॉर्ड स्तर पर होना चाहिए, ताकि लोकतंत्र की नींव और मजबूत हो सके।

निष्कर्ष

आज महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखों के ऐलान ने वर्षों से लटके लोकतांत्रिक सवाल को एक निर्णायक मोड़ दिया है। 15 जनवरी 2026 को BMC और अन्य नगर निगमों का मतदान होने वाला है, जो राज्य की राजनीति को नई दिशा देगा और नागरिकों की भागीदारी को सशक्त करेगा। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता, समय पर कार्यान्वयन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का सम्मान ही लोकतंत्र को आगे बढ़ाता है।



बीजिंग/ढाका: चीन के स्वदेशी लड़ाकू विमान J-10C को अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक के बाद एक झटके लगते नजर आ रहे हैं।

चीन के J-10C को लगातार झटके: इंडोनेशिया के बाद बांग्लादेश ने भी बनाई दूरी, यूरोफाइटर टाइफून पर टिकी नजर

इंडोनेशिया के बाद अब बांग्लादेश ने भी चीनी J-10C से दूरी बनाते हुए यूरोफाइटर टाइफून में दिलचस्पी दिखाई है। इसे चीन के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और रक्षा-निर्यात से जुड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश वायुसेना (BAF) ने यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमान की खरीद को लेकर लेटर ऑफ इंटेन्ट (LoI) पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रस्तावित योजना के तहत बांग्लादेश 12 से 16 यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट खरीद सकता है। अगर यह सौदा अंतिम रूप लेता है, तो बांग्लादेश इटली, जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन के कंसोर्टियम द्वारा निर्मित इस 4.5-जेनरेशन फाइटर जेट को ऑपरेट करने वाला 11वां देश बन

जाएगा।

यह कदम कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बांग्लादेश न केवल पहला दक्षिण एशियाई देश होगा जो यूरोफाइटर टाइफून को अपनाएगा, बल्कि यूरोप और मध्य पूर्व के बाहर ऐसा करने वाला भी पहला देश बनेगा। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक, मल्टी-रोल क्षमता, एडवांस्ड एवियोनिक्स और इंटरऑपरेबिलिटी के मामले में यूरोफाइटर टाइफून, चीनी J-10C पर भारी पड़ता है।

चीन पिछले कुछ समय से J-10C को आक्रामक तरीके से वैश्विक बाजार में प्रमोट कर रहा है। पाकिस्तान के साथ मिलकर इसे “राफेल किलर” के रूप में पेश करने की कोशिश भी

की गई, लेकिन इन दावों के बावजूद चीन को अब तक पाकिस्तान के अलावा कोई ठोस निर्यात ग्राहक नहीं मिल पाया है।

इधर, इंडोनेशिया ने भी J-10C को लेकर अंतिम फैसला टाल दिया है। वहां के रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि चीनी, पश्चिमी और क्षेत्रीय विमानों का मूल्यांकन जारी है और अभी किसी सौदे पर मुहर नहीं लगी है।

विशेषज्ञों के अनुसार, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों का झुकाव यूरोफाइटर टाइफून की ओर बढ़ना, चीन के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि केवल आक्रामक प्रचार के दम पर वैश्विक हथियार बाजार में भरोसा नहीं जीता जा सकता।

World News | पहलगाम आतंकी हमले में NIA की चार्जशीट

पहलगाम आतंकी हमले में NIA की चार्जशीट, पाकिस्तान प्रायोजित साजिश का खुलासा, लश्कर-TRF के 7 आरोपी नामजद

नई दिल्ली | जम्मू-कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार को जम्मू की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। एनआईए ने इस मामले में मारे गए तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों सहित कुल सात लोगों को आरोपी बनाया है। चार्जशीट में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और उसके शैडो संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) की भूमिका को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है।



एनआईए ने इस हमले को पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित और धर्म के आधार पर अंजाम दिया गया आतंकी हमला बताया है, जिसमें 25 पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिक की मौत हुई थी। 1597 पन्नों की चार्जशीट में हमले की साजिश, योजना, आतंकियों की भूमिका और ठोस सबूतों का विस्तृत विवरण दिया गया है।

चार्जशीट में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठे लश्कर हैंडलर साजिद जट्ट उर्फ हबीबुल्ला मलिक उर्फ साजिद लंगड़ा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। एनआईए के अनुसार, साजिद पीओके के कोटली क्षेत्र में सक्रिय लश्कर के ‘कोटली विंग’ है।

का ऑपरेशनल कमांडर है और जम्मू-कश्मीर में TRF की गतिविधियों को निर्देशित कर रहा था। इस मॉड्यूल में रफीक नाई उर्फ सुल्तान और रियाज अहमद की भी अहम भूमिका बताई गई है।

आरोप पत्र में ‘ऑपरेशन महादेव’ के तहत जुलाई 2025 में श्रीनगर के दाचीगाम में मारे गए तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों—फैसल जट्ट उर्फ सुरेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ जिब्रान और हमजा अफगानी—के नाम भी शामिल हैं।

एनआईए ने बताया कि करीब आठ महीने चली वैज्ञानिक जांच में हमले की साजिश के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े पाए गए। इसके अलावा, 22 जून 2025 को गिरफ्तार परवेज अहमद और बशीर अहमद जोधतद पर आतंकियों को पनाह और मदद देने का आरोप लगाया गया है।

सभी आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), शस्त्र अधिनियम और UAPA के तहत, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने सहित गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।

राज्यसभा | राज्यसभा में SIR पर सियासी घमासान

राज्यसभा में SIR पर सियासी घमासान, विपक्ष ने चुनाव आयोग को घेरा, देवेगौड़ा बोले– आरोप जारी रहे तो उल्टा नुकसान होगा



नई दिल्ली: राज्यसभा में सोमवार को चुनाव सुधार और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग पर पक्षपात, मतदाता सूची में विसंगतियों और चुनावी पारदर्शिता को कमजोर करने के आरोप लगाए, जबकि सरकार और उसके सहयोगी दलों ने SIR को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक बताया।

बहस की शुरुआत करते हुए AIADMK सांसद एम. थंबीदुरई ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की स्वच्छता लोकतंत्र की पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव के लिए बेहद ज़रूरी है।

जेडीएस सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे लगातार “वोट चोरी” के आरोप लगाते रहे, तो उन्हें राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सड़कों और मंचों पर मजाक उड़ाया जा रहा है, जबकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर में विपक्ष ने कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। देवेगौड़ा ने यह भी कहा कि पंडित नेहरू के समय भी चुनावी प्रक्रिया में खामियां थीं।

सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटान ने SIR पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इसका

नाम “अमित शाह इंटेसिव रिविजन” होना चाहिए। हालांकि उन्होंने 2014 में FCRA संशोधन के लिए कांग्रेस और भाजपा—दोनों को जिम्मेदार ठहराया। बीआरएस सांसद आर. सुरेश रेड्डी ने चुनावी घोषणापत्र पूरे न करने को मतदाताओं के साथ धोखा बताया और दलबदल विरोधी कानून में सुधार की मांग की।

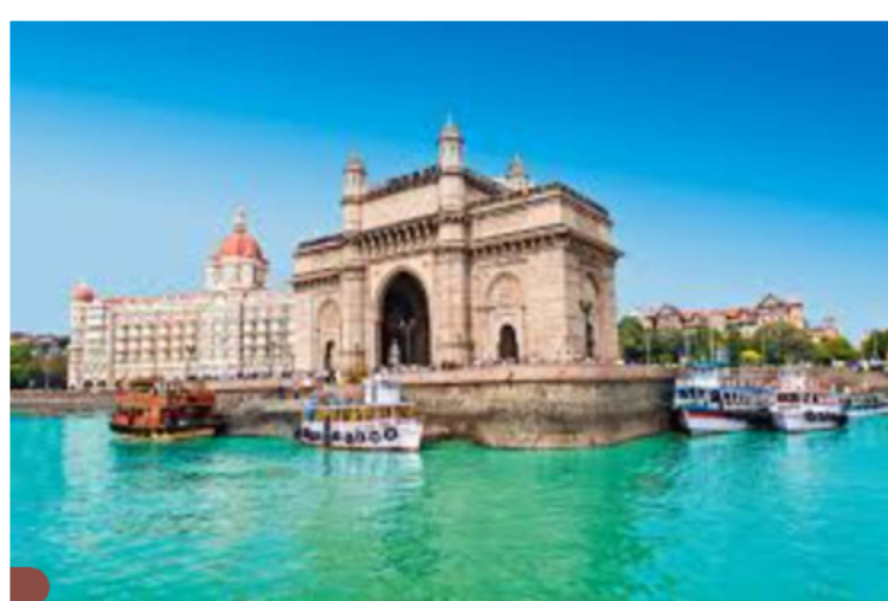
जेडीयू सांसद संजय झा ने 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि खंडित जनादेश के बावजूद नीतीश कुमार को समर्थन मिला था, लेकिन यूपीए सरकार ने आधी रात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। उन्होंने इसे “अभूतपूर्व स्थिति” करार दिया।

कांग्रेस सांसद दिव्जय सिंह ने सवाल उठाया कि साल में चार बार मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण होता है, तो SIR की जरूरत क्यों है। उन्होंने आरएसएस और गृह मंत्री अमित शाह

को लेकर भी सवाल किए। इस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने जवाब देते हुए कहा कि दिव्जय सिंह ने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है और अमित शाह ने स्वयं कहा है कि वे आरएसएस से जुड़े हैं और इस पर उन्हें गर्व है।

आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक ने राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की मांग उठाई, जबकि कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने SIR को “सेलेक्टिव आइडियोलॉजिकल रिमूवल” करार दिया। भाजपा सांसद समिक भट्टाचार्य ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण का हवाला देते हुए अवैध इमीग्रेशन के खिलाफ सख्त रुख की बात कही। बहस के अंत में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी अंबेडकर के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है।





महाराष्ट्र विशेष

कोकण > पश्चिम महाराष्ट्र > मराठवाड़ा > विदर्भ



नंदिग्राम टाइम्स

Tuesday 16th December 2025 वर्ष - 9 , अंक 230, पृष्ठ 03

नगर निगम चुनावों से पहले ठाणे-नागपुर में निधि का वर्षाव: ठाणे को ₹202 करोड़, नागपुर को ₹134 करोड़ मंजूर



संवाददाता |

मुंबई: महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के आगामी चुनावों से पहले राज्य सरकार ने ठाणे और नागपुर नगर निगमों को बड़े पैमाने पर निधि मंजूर कर दी है। आचारसंहिता लागू होने से पहले जारी फैसले के तहत ठाणे महानगरपालिका को ₹202 करोड़ का विकास कार्यों के लिए बजट आवंटित किया गया है, वहीं नागपुर नगर निगम को ₹134 करोड़ का वित्तीय सहयोग दिया गया है। ये निधि सीधे वित्त तथा नियोजन विभाग और नगर विकास विभाग द्वारा जारी की गई है, जिसका उद्देश्य नगर मूलभूत सुविधाओं, साफ-सफाई, सड़क निर्माण और अन्य शहरी विकास कार्यों को प्रोत्साहन देना बताया गया है।

आचारसंहिता लागू होने से पहले राज्य सरकार ने 51 शासन निर्णय जारी किए हैं, जिनमें से कई महापालिकाओं को विशेष तौर पर विकास कार्य के लिए निधि प्रदान करने की व्यवस्था है। इसके तहत नासिक, कल्याण-डोंबिवली, सांगली-मिरज-कुपवाड़ा समेत कई नगरपालिकाओं को भी अतिरिक्त बजट दिया गया है और मुंबई महानगरपालिका को भी ₹36 करोड़ वितरित किए गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह निधि आवंटन चुनावी तैयारियों और विकास कार्य को तेज करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, ताकि नागरिक मुद्दों पर जोर देकर मतदाताओं का समर्थन हासिल किया जा सके।

ELECTION | महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव का बजा बिगुल,

महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव का बजा बिगुल, 15 जनवरी को वोटिंग, 16 को नतीजे

● NEWS AGENCY

मुंबई: महाराष्ट्र में लंबे समय से टले हुए नगर निगम चुनाव अब तय हो गए हैं। राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुंबई समेत राज्य की 29 नगर निगमों के चुनाव की तारीखों की घोषणा की। इसके अनुसार वोटिंग 15 जनवरी, 2026 को होगी और मतगणना 16 जनवरी, 2026 को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्टेट इलेक्शन कमीशन को 31 जनवरी, 2026 से पहले चुनाव कराने का आदेश दिया था। इसके बाद आयोग ने शेड्यूल की घोषणा की। मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर, नवी मुंबई और छत्रपति संभाजीनगर समेत 29 शहरों में चुनाव होंगे।



राज्य चुनाव आयोग के कमिश्नर दिनेश वाघमारे ने बताया कि 23 दिसंबर से 30 दिसंबर, 2025 तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। 31 दिसंबर को स्क्रूटनी होगी और नाम वापस लेने की अंतिम

तारीख 2 जनवरी, 2026 है। उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट 3 जनवरी, 2026 को जारी की जाएगी। वाघमारे ने कहा कि इनमें से 27 नगर निगमों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका

है। मुंबई समेत 18 नगर निगमों का टर्म 2022 में समाप्त हो गया था, जबकि चार नगर निगमों का टर्म 2023 में समाप्त हुआ। नगर निगमों का डिवीजन अनुसार विवरण:

*मुंबई MMRDA डिवीजन: मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, भिवंडी, मीरा-भायंदर, उल्हासनगर, पनवेल।
*वेस्टर्न महाराष्ट्र डिवीजन: पुणे, पिंपरी-चिंचवाड़, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, इचलकरंजी।
*नॉर्थ महाराष्ट्र डिवीजन: नासिक, अहिल्यानगर, धुले, जलगांव, मालेगांव।
*मराठवाड़ा डिवीजन: छत्रपति संभाजीनगर, लातूर, नांदेड़-वाघाला, परभणी, जालना।
*विदर्भ डिवीजन: नागपुर, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर।

राज्य में यह चुनाव लंबे समय से टल रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और चुनाव आयोग की तैयारी के बाद सभी 29 नगर निगमों में मतदान निश्चित हुआ है।

किशोरी पेडणेकर ने उठाया चुनाव आयोग पर सवाल, मतदाता सूची में गड़बड़ी पर जताई चिंता

मुंबई: शिवसेना (उद्धव नेतृत्व) की नेता और पूर्व मुंबई महापौर किशोरी पेडणेकर ने महाराष्ट्र में 29 नगर निगम चुनावों की घोषणा के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में गड़बड़ी अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, बावजूद इसके चुनाव कराने की घोषणा की गई। पेडणेकर ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष चुनाव प्रक्रिया को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है।



उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी मतदाता सही सूची में शामिल हों और किसी प्रकार की अनियमितता न हो। पेडणेकर ने चेतावनी दी कि यदि सूची में त्रुटियों के बावजूद चुनाव कराए गए, तो इसका उल्टा असर पड़ सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने 15 जनवरी को वोटिंग और 16

जनवरी को नतीजों की घोषणा की थी। पेडणेकर ने यह सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना आयोग की जिम्मेदारी है। शिवसेना नेता ने यह भी जोर दिया कि लोकतंत्र में मतदाता की सुरक्षा और उनकी भागीदारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

उनका कहना है कि सत्ताधारी दल द्वारा चुनाव प्रक्रिया में दबाव या सूची में गड़बड़ी लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। यह मामला राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि चुनाव आयोग की तैयारी और मतदाता सूची की सटीकता को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

Maharashtra Politics | प्रकाश आंबेडकर की भविष्यवाणी:

प्रकाश आंबेडकर की भविष्यवाणी: अगले दो महीनों में भारत-पाकिस्तान युद्ध की संभावना



उल्हासनगर: वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने उल्हासनगर में आयोजित सभा में कहा कि अगले दो महीनों के भीतर

भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, चीन, इंग्लैंड और रूस जैसे देशों से हथियारों की आपूर्ति मिल रही है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहा है।

आंबेडकर ने चेतावनी दी कि यह युद्ध सामान्य जनता के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीतियों के खिलाफ हो सकता है। उन्होंने कहा कि देशवासियों को सतर्क रहना चाहिए और किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक जानकारी से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

सभा में उन्होंने उल्हासनगर महापालिका चुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि स्थानीय राजनीतिक हालात भी काफी तनावपूर्ण हैं। आंबेडकर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप और हथियारों की बढ़ती सप्लाई भारत-पाकिस्तान संबंधों में अस्थिरता पैदा कर सकती है। उन्होंने क्षेत्रीय नेताओं और नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की। विश्लेषकों का कहना है कि प्रकाश आंबेडकर का यह बयान न केवल राजनीतिक रूप से अहम है, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों और कूटनीतिक विशेषज्ञों के लिए भी सतर्कता का संकेत है। उन्होंने यह भी कहा कि

वर्तमान वैश्विक और क्षेत्रीय परिस्थितियां युद्ध की संभावना को बढ़ा सकती हैं, इसलिए सरकार को रणनीतिक और कूटनीतिक कदम तेजी से उठाने होंगे। आंबेडकर ने सभा में जोर देकर कहा कि जनता को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना और देश की सुरक्षा के प्रति सचेत रहना बेहद जरूरी है। उनकी इस भविष्यवाणी ने राजनीतिक और सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच नए संवाद को जन्म दिया है। यह बयान आगामी महीनों में भारत-पाकिस्तान संबंधों पर व्यापक चर्चा और रणनीतिक तैयारियों का संकेत देता है।

सुप्रिया सुळे का EVM पर भरोसा, कहा-चार बार इसी मशीन से चुनी गई हूँ

संवाददाता |

पुणे: सांसद सुप्रिया सुळे ने स्पष्ट किया कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर पूर्ण भरोसा है और वे इसे कभी सवाल के दायरे में नहीं लाएंगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने चार बार इसी मशीन के माध्यम से जनता की सेवा का मौका पाया है और यह साबित करता है कि EVM चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। सुळे के इस बयान का कांग्रेस में EVM विवाद के बीच विशेष महत्व है, क्योंकि हाल के दिनों में पार्टी में इस विषय को लेकर मतभेद बढ़े हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा के लिए EVM जैसे तकनीकी उपकरण जरूरी हैं और जनता के मत की सुरक्षा के लिए यह अत्यंत भरोसेमंद माध्यम है।



नागपूर: बहुप्रतिक्षित नागपूर महानगरपालिका चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं।

नागपूर महापालिका चुनाव: बीजेपी का 'विजयी चौकार' या कांग्रेस की वापसी बनेगी गेमचेंजर?

2007 से सत्ता में रहे बीजेपी ने इस चुनाव में 120 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। पार्टी का 'मिशन 120' विजय चौकार मारने पर केंद्रित है। वहीं कांग्रेस इस क्षेत्र में अपनी वापसी के लिए जोर लगा रही है और मतदाताओं का विश्वास वापस पाने के प्रयास कर रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी की जीत चार प्रमुख वादों में उनके लिए बढ़त साबित हो सकती है, वहीं कांग्रेस के मजबूत प्रदर्शन से शिवसेना और NCP की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। नागपुर में एक समय कई

इलाकों में शिवसेना का प्रभाव अधिक था, लेकिन पिछले चुनावों में पार्टी की पकड़ कमजोर हुई है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह चुनाव केवल सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि नागपुर में राजनीतिक संतुलन बदलने वाला मील का पत्थर साबित होगा। बीजेपी की रणनीति स्थानीय विकास और प्रशासनिक मुद्दों पर केंद्रित रही है, जबकि कांग्रेस स्थानीय नेताओं और क्षेत्रीय मुद्दों पर जोर दे रही है। शिवसेना और NCP के लिए यह

चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है। अगर बीजेपी और कांग्रेस में से किसी एक की पकड़ मजबूत होती है तो अन्य दलों को नए समीकरणों के अनुसार रणनीति बदलनी पड़ेगी। इस चुनाव के नतीजे नागपुर में भविष्य की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण संकेत देंगे।

इस बार का चुनाव ना सिर्फ शहर की राजनीति बल्कि राज्य में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए भी राजनीतिक दिशा तय करेगा। नागपुर महानगरपालिका चुनाव का पूरा नतीजा 16 जनवरी, 2026 को घोषित होगा।



नांदेड के उपनिबंधक का आदेश रद्द, नंदिग्राम सहकारी गृहनिर्माण संस्था के पूर्व अध्यक्ष को राहत

नांदेड : नांदेड शहर की प्रतिष्ठित नंदिग्राम सहकारी गृहनिर्माण संस्था से जुड़े अध्यक्ष अपात्रता मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। लातूर स्थित विभागीय सहनिबंधक कार्यालय ने नांदेड के उपनिबंधक द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है। इस निर्णय से संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष राजेश सोनकांबळे को बड़ी राहत मिली है।

शारदानगर स्थित नंदिग्राम सहकारी गृहनिर्माण संस्था के संचालक मंडल का चुनाव नवंबर 2023 में संपन्न हुआ था। 17 सदस्यीय कार्यकारिणी में से 16 सदस्य निर्वाचित हुए थे, जिनमें प्रा. डॉ. राजेश सोनकांबळे के पैनल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। इसके बाद 15 अक्टूबर 2023 को सर्वसम्मति से राजेश सोनकांबळे का संस्था के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चयन किया गया था। उन्होंने लगभग एक वर्ष तक अध्यक्ष के रूप में संस्था का कार्य सुचारु रूप से संचाला।

इस बीच संस्था के संचालक तेजवंतसिंह बलवंतसिंह पुंड ने 16 जनवरी 2025 को नांदेड के

नांदेड में विकास को नई गति, गणेशनगर और प्रभाग 8 में करोड़ों के कार्यों का भूमिपूजन

नांदेड | नांदेड शहर के विकास को लेकर भाजपा की डबल इंजन सरकार प्रतिबद्ध है और शहर का चेहरा-मोहरा बदलने के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। यह प्रतिपादन राज्यसभा सांसद डॉ. अजित गोपछडे ने गणेशनगर, प्रभाग क्रमांक 6 में आयोजित विकास कार्यों के भूमिपूजन समारोह में किया।

14 दिसंबर को सुबह 10 बजे बजाजनगर स्थित हनुमान मंदिर परिसर में प्रभाग क्रमांक 6 में लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले 23 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण संपन्न हुआ। डॉ. गोपछडे ने कहा कि मिलिंदभाऊ देशमुख के नेतृत्व में गणेशनगर प्रभाग के समग्र विकास की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बढ़ती जनसंख्या और नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित विकास कार्य किए जा रहे हैं।



इस अवसर पर मराठवाड़ा संगठन मंत्री संजय कौडगे, पूर्व मंत्री डी.पी. सावंत, महानगराध्यक्ष अमरनाथ राजुरकर, पूर्व महानगराध्यक्ष प्रविण साले सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। कार्यक्रम में बड़ी

करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से सीसी सड़क और नाली निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया गया। शिवाजीनगर में स्वातंत्र्य सैनिक स्व. आबासाहेब लहानकर चौक से डॉ. आंबेडकर नगर पाटी तक, श्रावस्ती नगर में मुख्य नाले से बुद्ध विहार तक तथा लालवाड़ी अंडरग्राउंड ब्रिज से कल्पतरु हॉस्पिटल रोड तक सीसी सड़क निर्माण कार्य शुरू किए गए।

इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डी.पी. सावंत, मराठवाड़ा संगठन मंत्री संजय कौडगे, महानगराध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अमरनाथ राजुरकर, पूर्व महापौर मोहिनी येवनकर सहित अनेक पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इन विकास कार्यों से शहर के विभिन्न प्रभागों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

शिक्षा संचालक डॉ. महेश पालकर ने | सूची 17 दिसंबर तक प्रस्तुत करने के निर्देश चेंज रिपोर्ट विवादों पर प्रशासन सक्रिय: अटकी शैक्षणिक संस्थाओं की सूची तैयार करने की प्रक्रिया तेज़

नांदेड | जिले में शैक्षणिक संस्थाएँ धीरे-धीरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का रूप लेती जा रही हैं। शिक्षा पर बढ़ते खर्च से अभिभावक आर्थिक रूप से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर इसी बाजारीकरण के चलते कई शैक्षणिक संस्थाएँ आंतरिक विवादों में उलझ गई हैं। संस्था संचालकों के बीच मतभेद के कारण अनेक शैक्षणिक संस्थाओं के 'चेंज रिपोर्ट' लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं। अब ऐसे मामलों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर युद्धस्तर पर जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

शिक्षा अनिवार्य होने के बावजूद उसका बाजारीकरण तेज़ी से बढ़ा है। भारी भरकम फीस की वसूली आम बात हो गई है। निजीकरण के माध्यम से शिक्षा सस्ती और सुलभ होने का दावा



किया गया था, लेकिन हकीकत इसके उलट नज़र आ रही है। मान्यता प्राप्त करना, भवन निर्माण और अत्यधिक शुल्क वसूलने वाली संस्थाओं का जाल फैलता गया है। अनुदान पात्र शैक्षणिक संस्थाओं में भी अलग तरह की खींचतान देखने को मिल रही है।

कई संस्थाओं में पदाधिकारियों के अलग-अलग गुट एक-दूसरे के

विरोध में खड़े हैं। एक गुट द्वारा चेंज रिपोर्ट दाखिल की जाती है, तो दूसरा गुट उस पर आपत्ति दर्ज करा देता है। इसका असर विद्यालय के शैक्षणिक माहौल पर भी पड़ रहा है। प्रधानाध्यापक और शिक्षक भी गुटबाजी में बँटते नज़र आ रहे हैं, जिससे शिक्षा का वातावरण प्रभावित हो रहा है। इसी पृष्ठभूमि में संस्था अधिनियम 1860 और मुंबई सार्वजनिक न्यास अधिनियम

1950 के अंतर्गत पंजीकृत, तथा जिन शैक्षणिक संस्थाओं की कार्यकारिणी को लेकर विवाद हैं और जिनके चेंज रिपोर्ट लंबित हैं, उनकी सूची तैयार की जा रही है। विभागीय शिक्षा उपसंचालक के मार्गदर्शन में यह कार्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अधिकारियों को सौंपा गया है।

17 दिसंबर तक समय-सीमा जिन शैक्षणिक संस्थाओं में विवाद के कारण चेंज रिपोर्ट लंबित हैं, उनकी सूची 17 दिसंबर तक प्रस्तुत करने के निर्देश शिक्षा संचालक डॉ. महेश पालकर ने दिए हैं। जो अधिकारी तय समय में सूची प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हें 19 दिसंबर को स्वयं जानकारी लेकर संचालनालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

हिमायतनगर तालुका में पाँच माह से रुके आवास अनुदान के हप्ते, 900 घर अधूरे

हिमायतनगर (संवाददाता)

हिमायतनगर तालुका क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना और शबरी आवास योजना के अंतर्गत घरकुल स्वीकृत किए गए थे। योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में शुरूआती 15 हजार रुपये की पहली किस्त जमा हुई, जिसके बाद कई लाभार्थियों ने निर्माण कार्य शुरू किया।

हालांकि, बीते पाँच महीनों से कुछ लाभार्थियों को दूसरी तो कुछ को तीसरी किस्त नहीं मिली है। इसके चलते तालुका में करीब 900 घरकुलों का निर्माण कार्य अधर में लटक गया है। अधूरे निर्माण के कारण लाभार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाभार्थियों का कहना है कि योजना के सभी मापदंड पूरे करने के बावजूद अनुदान की



अगली राशि के लिए पंचायत समिति के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। संबंधित अधिकारियों से पूछताछ करने पर बताया जा रहा है कि शासन की ओर से अभी तक निधि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए आगे की किस्त जारी नहीं की जा सकती। सरकार की ओर से प्रत्येक लाभार्थी को कुल 1 लाख 38 हजार रुपये का अनुदान देने का प्रावधान है, लेकिन मौजूदा महंगाई में यह राशि भी घर की नींव डालने के लिए पर्याप्त नहीं है।

इसके बावजूद कई लाभार्थियों ने कर्ज लेकर या अपनी सीमित बचत से निर्माण कार्य शुरू किया था। अब निधि न मिलने के कारण निर्माण पूरी तरह ठप पड़ा है। लाभार्थी दूर-दराज़ से पंचायत समिति के निर्माण विभाग में आकर निराश लौट रहे हैं। निर्माण का उचित समय निकल रहा है, लेकिन धनाभाव के चलते घरकुल का काम रोकना उनकी मजबूरी बन गई है। लाभार्थियों ने मांग की है कि अनुदान की शेष राशि शीघ्र जारी की जाए, ताकि अधूरे पड़े घरों का निर्माण पूरा हो सके और उन्हें आवास का अधिकार मिल सके।

कंधार में लिपिक की शिकायत के बाद तहसीलदार ने दिए गहन जांच के आदेश

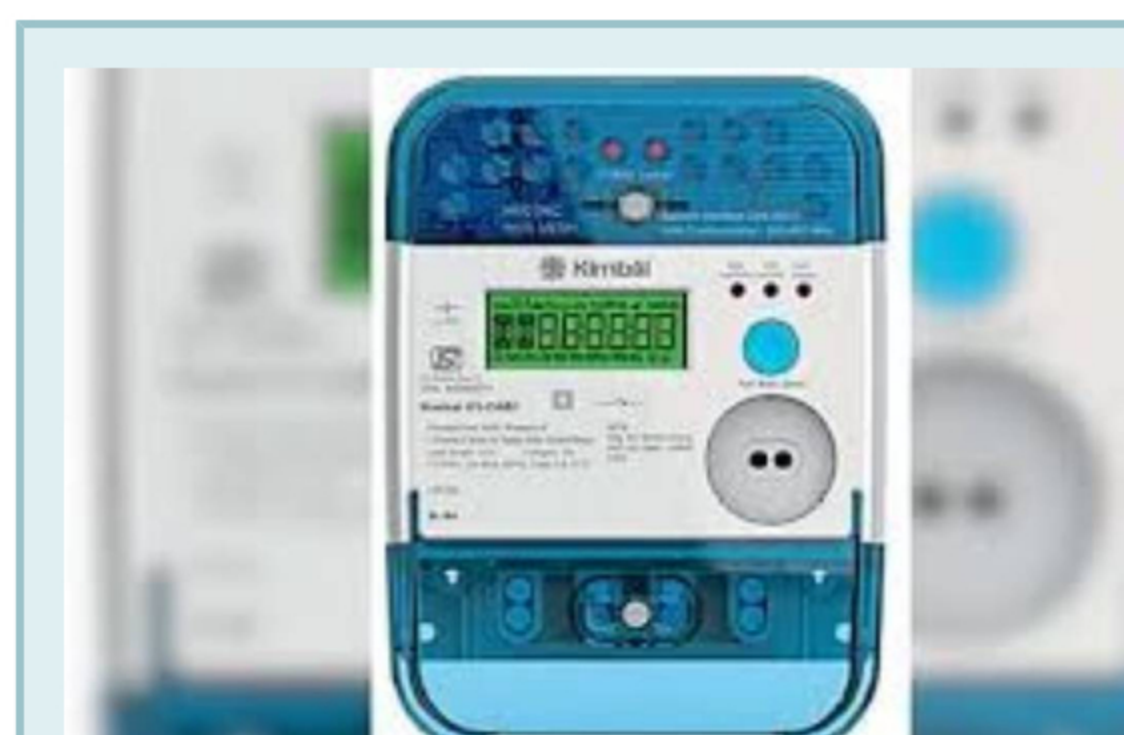
कंधार | (संवाददाता) : कंधार तहसील कार्यालय में कार्यरत एक राजस्व लिपिक के खिलाफ गंभीर आरोपों की शिकायत सामने आने के बाद तहसीलदार ने मामले की सखोल (गहन) जांच के आदेश दिए हैं। पद के दुरुपयोग, नागरिकों के कार्यों में जानबूझकर विलंब, अभद्र व्यवहार, अनुशासनहीनता तथा अनधिकृत अनुपस्थिति जैसे आरोपों को लेकर संबंधित लिपिक के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की मांग की गई थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कंधार तहसील कार्यालय में राजस्व सहायक पद पर कार्यरत तिरुपति मुंगरे के कार्यशैली को लेकर लंबे समय से शिकायतें सामने आती रही हैं। कुछ दिन पूर्व एक वरिष्ठ अधिकवक्ता के साथ हुए विवाद के कारण तहसील कार्यालय में तनाव की स्थिति भी बनी थी। उस दौरान राजस्व कर्मचारी संघ और अधिकवक्ता संघ आमने-सामने आ गए थे। यह विवाद कार्यालयीन कार्य ठप होने से लेकर पुलिस थाने तक पहुंच गया था। अब एक बार फिर मुंगरे पर लगातार अनुशासनहीनता, कार्यालयीन कार्यों में लापरवाही, पद का दुरुपयोग तथा

कार्यालयीन समय का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि संबंधित लिपिक निर्धारित समय पर नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते, समय से पहले कार्यालय छोड़ देते हैं और हाजिरी लगाने के बाद निजी कार्यों के लिए बाहर जाते देखे जाते हैं। इसके कारण आम नागरिकों के कार्य लंबे समय तक लंबित रहते हैं।

शिकायतकर्ता अनेक गुणवंत कल्याणकस्तुरे ने तहसीलदार को दी गई लिखित शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि कार्यालयीन फाइलें बाहर ले जाकर काम निपटाने का प्रयास किया जाता है, जो नियमों के विरुद्ध है और पद के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। शिकायत में कथित अनियमितताओं से संबंधित सबूत उपलब्ध होने का भी उल्लेख किया गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कंधार तहसीलदार ने शिकायत की गहन जांच के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई किए जाने की संभावना जताई जा रही है।



नांदेड | नांदेड शहर में स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर महावितरण द्वारा नियुक्त निजी कंपनी के कर्मचारियों की ओर से खुलेआम अवैध वसूली किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। मीटर बदलने की प्रक्रिया महावितरण की आधिकारिक योजना का हिस्सा होने के बावजूद, कर्मचारियों द्वारा प्रति मीटर 300 से 1,000 रुपये तक की सीधी नकद मांग की जा रही है।

नांदेड शहर में स्मार्ट मीटर के नाम पर खुली वसूली, महावितरण की छवि पर सवाल

कई स्थानों पर उपभोक्ताओं को यह कहकर डराया जा रहा है कि "पैसे दिए बिना मीटर नहीं बदला जाएगा", जिससे आम नागरिकों में भारी नाराजगी फैल गई है।

बताया जा रहा है कि महावितरण हर वर्ष किसी न किसी कारण से मीटर बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है और अब स्मार्ट मीटर के नाम पर यह कार्य जबरन किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर से बिजली बिल पारदर्शी और कम आने के दावे किए गए थे, लेकिन इसके उलट शहर के कई उपभोक्ताओं को उपयोग से कई गुना अधिक बिजली बिल मिलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इससे स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली और

मंशा दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

नांदेड शहर में महावितरण द्वारा नियुक्त एजेंसी के माध्यम से बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि महज डेढ़ से दो वर्ष पहले जीनस पावर कंपनी के आधुनिक डिजिटल मीटर लगाए गए थे, जो अभी भी सुचारु रूप से कार्यरत थे। इसके बावजूद उन्हें हटाकर केन्स टेक्नोलॉजी कंपनी के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, शहर में करीब 1 लाख 30 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं, लेकिन इनके बदलाव के पीछे कोई ठोस और स्पष्ट कारण सामने नहीं आ रहा है। मीटर बदलने के बदले पैसे मांगने से

संबंधित एक ऑडियो रिकॉर्डिंग 'लोकमत' के हाथ लगी है, जिससे पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि मीटर बदलाव से महावितरण को करोड़ों रुपये का लाभ होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही उपभोक्ताओं से अतिरिक्त अवैध वसूली किए जाने के आरोप भी मजबूत हो गए हैं।

इस पूरे प्रकरण से महावितरण की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गया है। उपभोक्ताओं की मांग है कि इस अवैध वसूली की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी कर्मचारियों और संबंधित एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आम जनता का विश्वास बहाल हो सके।